International Journal of Multidisciplinary Education and Research
ISSN: 2455-4588; Impact Factor: RJIF 5.12
Received: 18-04-2019; Accepted: 21-05-2019
www.educationjournal.in
Volume 4; Issue 4; July 2019; Page No. 74-75

ई–कामर्स नीति के मसौदे का विष्लेषणात्मक अध्ययन

Swati Singh Chauhan[1], Dr. Prabhakar Singh Sengar[2]
[1] Student, Department of Commerce, S.G.S. Govt. College Sidhi (A.P.S.U. Rewa) Madhya Pradesh, India
[2] Director, Department of Commerce, S.G.S. Govt. College Sidhi (A.P.S.U. Rewa) Madhya Pradesh, India

सरांश
भारत जैसे विकासशील देश में जहॉ पर ई–कामर्स का वर्तमान बिजनेस +25 है जो अनुमानतः अगले 10 वर्षो में में +200 बिलियन होने का अनुमान है, के लिये एक राष्ट्रीय नीति ई–कामर्स पर लाना बहुत ही आवश्यक है। इसी नई ई–कामर्स पालिसी के आने के पूर्व ही केवल और केवल इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार होने पर ही बड़ी–बड़ी कंपनियों जैसे अमेजन, वालमार्ट तथा अन्य और कंपनियों इतनी घबराई हुई है कि वे अमेरिका से गुहार लगा रही है कि वो इस मामले में अपना हस्तक्षेप करें अन्यथा इस कंपनियो का लाभ/बिजनेस प्रभावित होगा। इस ड्राफ्ट के अनुसार भारत सरकार घरेलू छोटे व्यापरियों तथा ज्यादा से ज्यादा रोजगार भारत में उत्पन्न कराने के पक्ष में नजर आ रही है। तथा इसके डाटा स्टोरेज की एक कापी को भी भारत में भी रखने जैसे निर्देश है। वाणिज्य मंत्रालय की एक कार्य समिति जिनके 70 सदस्यों ने मिलकर ई–कामर्स मसौदा तैयार किया है कि ई–कामर्स का सारा बाजार किस प्रकार से चलेगा, क्या नियम होने चाहिये, जिससे एक निष्पक्ष बाजार क्षेत्र का निर्माण किया जा सके। यही अभी एक मसौदा मात्र है। अर्थात विचारों का गंग्रह है कि किस प्रकार से यह कार्य करेगा। इस कार्य समिति के अध्यक्ष हमारे वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु जी थे। यह मसौदा अगस्त 2018 में बनाया गया है उस समय हमारे वाणिज्य मंत्री सुरेस प्रभु जी थे।

मूल शब्दः ई–कामर्स, इन्वेन्ट्री आधारित मॉडल, बाजार आधारित मॉडल, धोखाधड़ी खुफिया तंत्र, घर की कंपनिया।

प्रस्तावना (Introduction)
ई–कामर्स पालिसी के ड्राफ्ट के अनुसार अपने घरेलू बाजार को धोखाधड़ी जो आनलाइन प्लेटफार्म पर होती है उसे रोकने तथा सुचारू रूप से चलाने के लिये प्रेरित दिखाई देती है।

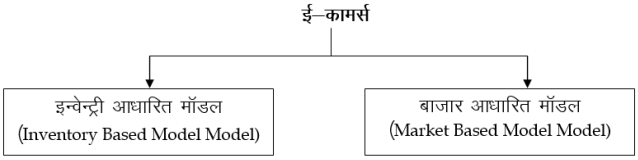

जब आप अमेजन से कुछ खरीदते हो तो आप डायरेक्टली अमेजन से नही खरीदते बल्कि अमेजन ने एक आनलाइन मंनी बना दी है और आप वास्तव में वहा एक विक्रेता से खरीद रहे हो इसे ही बाजार आधारित मॉडल कहते है जहॉ पर एक प्लेटफार्म होता है। जहॉ बहुत सारे विक्रेता उस प्लेटफार्म का उपयोग करते है अपने उत्पाद को बेचने के लिये और खरीददार वहॉ से खरीदते है।

इन्वेन्ट्री आधारित मॉडल
इन्वेन्ट्री आधारित मॉडल में कंपनी आपको किसी विक्रेता से नही मिलाती बल्कि सारा समान खुद ही बेचती है। विष्वप्रसिद्ध कंपनी अलीबाबा इन्वेन्ट्री आधारित मॉडल पर ही काम करती है। यदि हम अलीबाबा से कोई समान खरीदते है तो वो सीधे हमे वही से बेचे जाते है जो उसे कंपनी का मालिक है, डायरेक्ट उसी से खरीदते है उसमें बीच के विक्रेता नही होते है।

Table 1

वर्तमान ई–कामर्स बाजार भारत में	+25 बिलियन
आगामी 10 वर्षो में ई–कामर्स बाजार भारत में	+200 बिलियन
बाजार आधारित मॉडल	100: एफ.डी.आई.

अध्ययन का उद्देश्य (Aim of the Study)
- ई–कामर्स नीति के ड्राफ्ट के अध्ययन के निम्न उद्देश्य है
- इस नीति का विदेशी कंपनियों पर प्रभाव।
- इस नीति का घरेलू बाजार पर प्रभाव।
- नीति का उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला प्रभाव।
- अन्ततः नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव छोड़ेगी।
- क्या यह ड्राफ्ट इसी रूप में नीति का रूप लेगा या इसमें कुछ संशोधन किये जायेगें।

शोध क्रिया विधि (Research Methodology)
उक्त शोध पत्र में गुणात्मक तथा गणनात्मक दोनो ही शोध क्रिया विधि का इस्तेमाल किया गया है यह पता करने में कि इस ई–कामर्स नीति के ड्राफ्ट का विदेशी कंपनियों, देशी विक्रेताओं, उपभोक्ताओं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके नीति के रूप में बन जाने पर।

डाटा संग्रहण (Data Collection)
इस शोध पत्र में डाटा को मूलतः अप्रत्यक्ष तरीको इन्टरनेट तथा सरकारी वेबसाइट से प्राप्त किया गया है तथा कुछ स्वंय के अनुभवो द्वारा भी कुछ तथ्य रखे गये है, जो प्रत्यक्ष है।
- डायरेक्ट
- इनडायरेक्ट

राष्ट्रीय ई–कामर्स नीति की आवश्यकता (Necessity of E-Commerce Policy)
आज विश्व में सभी देश इन्टरनेट के द्वारा आपस में संचार तथा विभिन्न अन्य प्रकार के व्यवस्थाओं में सक्रिय है। जैसा कि हमे मालूम है कि भारत की आबादी इतनी बड़ी है जो कि बाहरी देशो की कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिये अच्छा अवसर व लाभप्रद प्रयोजन दिखाई देता है कि विदेशी कंपनिया भारत मे

आये और उन्हे यहॉ एक बहुत ही बड़े उपभोक्ता, बाजार में अपनी वस्तुए व सेवायें प्रदान कर अधिकारिक लाभार्जन करें। एक सर्वे के अनुसार वर्तमान में भारत की ई–कामर्स के माध्यम से व्यापार +25 बिलियन है जो कि अनुमानतः अगले 10 वर्षो मे +200 बिलियन होने का अनुमान है। यदि भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत नही भी बढ़ती है तब भी यहॉ की आबादी बढने के कारण इस क्षेत्र में व्यापार की संभावनायें है, क्योंकि भारत का मध्यम वर्गी परिवार बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और अगर आये में भी उतनी ही तेजी से बढोत्तरी होती है तो ई–कामर्स अगले 10 सालो मे +200 बिलियन से भी ज्यादा का होगा। इसलिये भारत सरकार इतने बड़े उपभोक्ता बाजार पर नियंत्रण रखने तथा उनसे सुचारू रूप से संचालन के लिये इस प्रकार की ई–कामर्स पालिसी को ला रही है। यद्यपि अभी वर्तमान में विकसित देशो में ई–कामर्स पालिसी कार्य करती है। आरै भारत भी इसी प्रकार का अपने देश मे कानून बनाना चाहती है। जिससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर उसका निपटारा किया जा सके। साथ ही साथ सरकार अपने देश की बढ़ती आबादी में बेरोजगारी की भी समस्या से निपटने के लिये उन्हे रोजगार के भी अच्छे अवसर उपलब्ध कराना चाहती है।

ई–कामर्स नीति के मसौदे के मुख्य बिन्दु (Main Highlights of E-Commerce Policy Draft)

- इन्वेन्ट्री आधरित मॉडल के एफडीआई के लिये विदेशी कंपनियों की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी अर्थात इसमें देशी कंपनियों की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत होनी चाहिये।
- 100 प्रतिशत भारत में बने समान ही बेचने होंगें इन्वेट्री आधारित मॉडल पर। (अर्थात दोनो ही तरीको में से ऐसे नही तो वैसी रोजगार भारत में होगी)
- बाजार आधारित मॉडल में इन बड़ी–बड़ी कंपनियों की जो इन–हाउस कंपनिया होती है यो जो सीधे अपने उपभोक्ता को माल बेचती हैं। उस पर बहुत बड़े–बड़े डिस्काउन्ट (छूट) देती है जिससे इनके सामने छोटे व्यापारी टिक नही पाते है वे अब ऐसा नही कर पायेंगी।
- उपभोक्ताओं के लिये सी.सी.पी.ए. सेन्ट्रल कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एथारिटी बनाइे जायेगी, जहॉ उनकी समस्याओं तथा उनके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की जा सकेगी।
- इससे बड़ी कंपनियों अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि को भी पता चलेगा की धोखाधड़ी कहॉ हो रही है और वे भी उस पर नकेल कर पायेंगें। क्यांकि कपंनियॉ, खुद भी ऐसा नही चाहती इससे उनका भी नाम खराब होता है।
- निवारण तंत्र (रीड्रेसल) – ये जो नियम बने है उसे भी चेक करने के लिये एक निवारण तंत्र होगा जो इनकी निगरानी करेगा कि एफ.डी.आई. कितनी आ रही है ई–कामर्स मे पेमेन्ट (भुगतान) आज के समय में ज्यादातर आनलाइन शॉपिंग में कश आन डिलेवरी भुगतान विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके लिये एक ऐसा (फ्राड इन्टेलिजेन्स मैकेनिस्म) बनाया जायेगा जिससे उपभोक्ता बिना झिझक अपने डेबिट कार्ड आदि की जानकारी भुगतान मे उपलब्ध करा सके अर्थात उसे इनती सुरक्षित भुगतान पद्धति उपलब्ध कराई जायेगी। और उपभोक्ता को अपने डाटा के खोने या चोरी होने का खतरा नही रहेगा।
- पहले उपभोक्ताओं का डाटा ये कंपनिया अपने दशो मे रखती थी अब इस ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि इन्हे अपने उपभोक्ताए के डाटा की एक कापी भारत में ही रखनी होगी। अर्थात इन कंपनियों को भारत में ही डाटा स्टोरेज के लिये भण्डारण गृह बनाने होगें।

ई–कामर्स नीति के ड्राफ्ट का निहतार्थ (Implication of nation e-commerce policy draft)

- भारत के छोटे विक्रेताओं को इसका फायदा मिलेगा।
- मेक इन इण्डिया को प्रोत्साहन मिलेगा।
- विदेशी कंपनियों को हर तरफ से नुकसान होगा अभी के मुकाबले उन्हे इन्वेन्ट्री आधारित मॉडल जो ये कंपनिया चाहती थी उसमे भी बहुत शर्ते लगा रखी है सरकार ने।
- भारत में डाटा स्टोर करने के कारण उन्हे (विदेशी कंपनियों) को पैसे खर्च करने होंगें। भारत में डाटा भण्डारण गृह बनाने में जिससे उनका फायदा और कम होगा और भारत में प्रत्यक्ष तरीके से राजगार वृद्धि होगी।
- ई–कामर्स पॉलिसी के ड्राफ्ट से विदेशी कंपनिया बहुत ही दुखी व परेशान दिखाई दे रही है क्योंकि उन्हे हर तरफ से अपना घाटा होते ही दिखाई दे रहा है।

निष्कर्ष (Conclusion)

आम उपभोक्ताओं की अगर बात करे तो शायद उन्हे उतनी आकर्षण छूट न मिल पाये जो उन्हे अभी मिलती है। इस वजह से इस ड्राफ्ट की आलेचना भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक छोटी मार्केट जिसे बस फ्री कर देना चाहिये उस बॉधा जा रहा है अर्थात बहुत तरह के रेगुलेशन लगाये जा रहे है। इस प्रकार के रेगुलेशन दीर्धकाल में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिये अच्छा नही होता है।

ई–कामर्स पालिसी के ड्राफ्ट को देख कर विशेषज्ञ ये कह रहे कि ऐसा लग रहा है कि भारत चाइना के मॉडल को अपना रहा है।

देखना यह होगा कि क्या यह ड्राफ्ट इसी रूप में नीति का रूप लेता है या इसमें कुछ संशोधन किये जाता है। यह ड्राफ्ट अपने वर्तमान रूप में कितना कारगार साबित होता है यह तो समय ही बतायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

1. अखबार (न्यूजपेपर)
2. https://commerce.gov.in
3. पत्रिकाओं में छपे विविध लेख
4. आनलाइन स्टडी ग्रुप के लेखो में लिये गये उदाहरण